



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 3

PART I—Section 3

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 03]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 18, 2016/आश्विन 26, 1938

No. 03]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 18, 2016/ASVINA 26, 1938

रक्षा मंत्रालय

(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2016

सं. 17(1)/2014/रक्षा(पेंशन/नीति).—वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के सातवें वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों पर दिनांक 8.9.2015 के संकल्प के तहत यथासंशोधित, संकल्प संख्या 1/1/2013-ई-III(ए), दिनांक 28.2.2014, में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है:-

"उन सिद्धांतों के लिए वांछनीय एवं व्यवहार्य परिवर्तनों की जांच करना, समीक्षा करना, विकास करना और सिफारिश करना जिनसे रक्षा बलों के कार्मिकों की परिलब्धियों की संरचना, रियायतें एवं नकद अथवा वस्तु रूप में सुविधाएं/लाभ तथा सेवानिवृत्ति लाभ शासित होने चाहिए और ऐसा करते हुए इन कार्मिकों के विशिष्ट पक्षों पर उपयुक्त बल देते हुए इन बलों की ऐतिहासिक एवं पारंपरिक समानताओं को ध्यान में रखा गया हो।"

2. आयोग ने 19 नवम्बर 2015 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। सरकार ने आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 10.2 में निहित रक्षा सेना से संबंधित कार्मिकों के पेंशन लाभों पर आयोग की सिफारिशों पर विचार किया है और यह निर्णय लिया है कि कुछ आशोधनों के अध्यधीन सिफारिशों को मोटे तौर पर स्वीकृत कर लिया जाएगा।

3. पेंशन लाभों से संबंधित आयोग की विस्तृत सिफारिशों और उन पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय इस संकल्प के साथ संलग्न सारणी में सूचीबद्ध हैं।

4. पेंशन लाभों से संबंधित संशोधित प्रावधान 01.01.2016 से प्रभावी होंगे।

के. दमयंती, संयुक्त सचिव

## अनुबंध

उन सिद्धांतों, जो रिपोर्ट के अध्याय 10.2 में निहित पेंशन संरचना तथा अन्य सेवांत लाभों को शासित करते हैं, के संबंध में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों तथा उन पर सरकार के निर्णयों को दर्शाने वाला विवरण

मद सं.	भूतपूर्व रक्षा सेना कार्मिकों के लिए सिफारिश	सरकार का निर्णय
1.	<p><b>सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की पेंशन में संशोधन:-</b></p> <p>आयोग ऐसे रक्षा कार्मिकों के लिए जो 1.1.2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए हों के पेंशन आकलन के लिए निम्नलिखित सिफारिश करता है:-</p> <p>(i) ऐसे सभी रक्षा कार्मिक जो 1.1.2016 (सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन की संभावित तारीख) से पहले सेवानिवृत्त हुए हों, का निर्धारण पहले आयोग द्वारा सिफारिश किए जा रहे वेतन मैट्रिक्स में, उस वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन के आधार पर, जिसमें वे सेवानिवृत्त हुए, मैट्रिक्स में उसके तदनुरूपी स्तर के न्यूनतम पर किया जाएगा। इस राशि को सेवानिवृत्त कार्मिक के काल्पनिक वेतन के निर्धारण के लिए उन 3% की दर पर वेतन वृद्धियों की संख्या में जोड़ा जाएगा जो सेवा में रहने के दौरान उस स्तर पर उसने प्राप्त की। 7<sup>वें</sup> केन्द्रीय वेतन आयोग की मैट्रिक्स में उसे काल्पनिक रूप से फिट करने के बाद आकलित राशि में सैन्य सेवा वेतन जोड़ा जाएगा। इस प्रकार से आकलित कुल राशि का 50% संशोधित पेंशन होगा।</p> <p>(ii) की जाने वाली दूसरी गणना निम्नलिखित है। छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के समय निर्धारित की गई पेंशन को 2.57 से गुणा किया जाएगा जिसे संशोधित पेंशन के लिए एक वैकल्पिक राशि का आकलन होगा।</p> <p>(iii) पेंशनभोगी इन दोनों में से जो भी अधिक हो, उसके हकदार होंगे।</p> <p>यह स्वीकार्य है कि उपर्युक्त गणना (i) के अनुसार पेंशन के निर्धारण में कुछ समय लग सकता है क्योंकि सेवानिवृत्ति स्तर में अर्जित वेतन वृद्धियों की संख्या का पता लगाने के लिए प्रत्येक पेंशनभोगी के रिकॉर्डों की जांच करनी होगी। अतः यह सिफारिश की जाती है कि 7<sup>वें</sup> केन्द्रीय वेतन आयोग की मैट्रिक्स में पेंशन के अंतिम रूप से निर्धारित किए जाने तक पेंशन की प्रथम बार गणना उपर्युक्त सूत्र (ii) के अनुसार निर्धारित की जाए।</p> <p>(रिपोर्ट का पैरा 10.2.87 और 10.2.88)</p>	<p>पेंशन संशोधन के संबंध में 7<sup>वें</sup> केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित दोनों विकल्पों को कार्यान्वयन की व्यवहार्यता की शर्त पर स्वीकार किया। 2.57 के फिटमेंट गुणक के आधार पर दूसरे विकल्प के कार्यान्वयन का प्रयोग करते हुए 31.12.2015 को आहरित पेंशन की गुणा करते हुए तत्काल पेंशन में संशोधन किया जाए। यदि समिति, जिसमें अध्यक्ष के रूप में सचिव (पेंशन) तथा सदस्य (स्टाफ) रेलवे बोर्ड, सदस्य (स्टाफ) डाक विभाग, अपर सचिव तथा एफए गृह मंत्रालय तथा लेखा महानियंत्रक सदस्य के रूप में शामिल हों, द्वारा जांच के बाद पहले विकल्प का कार्यान्वयन व्यवहार्य पाया जाए तो पहले विकल्प को लागू किया जाए।</p>
2.	<p><b>पेंशन, परिवार पेंशन तथा विशेष परिवार पेंशन की दरें –</b></p> <p>आयोग जेसीओ/ओआर के लिए पेंशन की दर में किसी और वृद्धि की सिफारिश नहीं करता है। (पैरा 10.2.22)</p> <p><b>वर्धित परिवार पेंशन</b> में सिविलियन अथवा रक्षा पेंशनभोगियों के लिए आयोग द्वारा किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं की जा रही है। (पैरा 10.2.33)</p> <p>आयोग द्वारा <b>विशेष परिवार पेंशन</b> की मौजूदा दर में किसी और वृद्धि की सिफारिश नहीं की गई है। (पैरा 10.2.35)</p>	स्वीकृत।
3.	<p><b>वृद्ध पेंशनभोगियों के लिए अतिरिक्त पेंशन तथा परिवार पेंशन -</b></p> <p>आयोग द्वारा बढ़ती हुई आयु के साथ अतिरिक्त पेंशन तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन की मौजूदा दर में किसी वृद्धि की सिफारिश नहीं की गई है। (पैरा 10.2.24)</p>	स्वीकृत।

	आयोग द्वारा बढ़ती हुई आयु के साथ अतिरिक्त पेंशन तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन की मौजूदा दर में किसी वृद्धि की सिफारिश नहीं की गई है। (पैरा 10.2.37)																		
4.	<b>2006 से पूर्व के ऑनरेरी नायब सूबेदार -</b> आयोग को ऐसे मुद्दे को पुनः खोलने में कोई गुणता नजर नहीं आई जिसका ठीक समय समाधान पहले ही हो गया है। अतः इस संबंध में किसी बदलाव की सिफारिश नहीं की गई है। (पैरा 10.2.26)	स्वीकृत।																	
5.	<b>रक्षा सुरक्षा कोर (डीएससी) कार्मिक -</b> आयोग रक्षा सुरक्षा कोर के कार्मिकों को दूसरी पेंशन की हकदारी के लिए अर्हकता सेवा में 15 वर्ष से कमी करके 10 वर्ष किए जाने की सिफारिश नहीं करता है। (पैरा 10.2.28)	स्वीकृत।																	
6.	<b>अर्हकता सेवा के लिए पेंशन में कमी करना -</b> आयोग पाता है कि पेंशन आकलन उचित है तथा प्रादेशिक सेना कार्मिकों की पेंशन के संबंध में मौजूदा व्यवस्थाओं की पुनरीक्षा के लिए कोई औचित्य नहीं देखता है। (पैरा 10.2.30)	स्वीकृत।																	
7.	<b>परिवार पेंशन के आकलन में युद्ध घायल अंश/निशक्तता अंश को शामिल किया जाना -</b> आयोग ने परिवार पेंशन के आकलन में युद्ध घायल अंश/निशक्तता अंश को शामिल किए जाने के संबंध में मौजूदा प्रावधानों में किसी अन्य बदलाव की सिफारिश नहीं की है। (पैरा 10.2.39)	स्वीकृत।																	
8.	<b>निशक्तता पेंशन की दर में वृद्धि -</b> आयोग का यह सुविचारित मत है कि छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग के बाद कार्यान्वित व्यवस्था को समाप्त किए जाने की आवश्यकता है और स्लैब आधारित प्रणाली को वापिस लाने की सिफारिश करता है। शतप्रतिशत निशक्तता के लिए निशक्तता अंश की स्लैब दरें निम्नलिखित होंगी :- <table border="1" data-bbox="289 1138 982 1591"> <thead> <tr> <th>रैंक</th><th>स्तर</th><th>प्रतिमाह दर (आईएनआर)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>सैन्य अफसर</td><td rowspan="2">10 तथा अधिक</td><td rowspan="2">27000</td></tr> <tr> <td>ऑनरेरी कमीशनप्राप्त अफसर</td></tr> <tr> <td>सूबेदार मेजर/समकक्ष</td><td rowspan="3">6 से 9</td><td rowspan="3">17000</td></tr> <tr> <td>सूबेदार/समकक्ष</td></tr> <tr> <td>नायब सूबेदार/समकक्ष</td></tr> <tr> <td>हवलदार/समकक्ष</td><td rowspan="3">5 से कम</td><td rowspan="3">12000</td></tr> <tr> <td>नायक/समकक्ष</td></tr> <tr> <td>सिपाही/समकक्ष</td></tr> </tbody> </table> (पैरा 10.2.55)	रैंक	स्तर	प्रतिमाह दर (आईएनआर)	सैन्य अफसर	10 तथा अधिक	27000	ऑनरेरी कमीशनप्राप्त अफसर	सूबेदार मेजर/समकक्ष	6 से 9	17000	सूबेदार/समकक्ष	नायब सूबेदार/समकक्ष	हवलदार/समकक्ष	5 से कम	12000	नायक/समकक्ष	सिपाही/समकक्ष	स्वीकृत।
रैंक	स्तर	प्रतिमाह दर (आईएनआर)																	
सैन्य अफसर	10 तथा अधिक	27000																	
ऑनरेरी कमीशनप्राप्त अफसर																			
सूबेदार मेजर/समकक्ष	6 से 9	17000																	
सूबेदार/समकक्ष																			
नायब सूबेदार/समकक्ष																			
हवलदार/समकक्ष	5 से कम	12000																	
नायक/समकक्ष																			
सिपाही/समकक्ष																			
9.	<b>निशक्तता कवर में वृद्धि -</b> आयोग 20 प्रतिशत से अधिक निशक्तता के लिए समयपूर्व मामले/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मामलों सहित निशक्तता के साथ सेवानिवृत्त होने वाले सभी कार्मिकों के लिए निशक्तता की ब्राड-बैंडिंग की सिफारिश करता है। (पैरा 10.2.57)	स्वीकृत।																	
10.	<b>निशक्तता/युद्ध घायल पेंशन के लिए अतिरिक्त वृद्धावस्था पेंशन लागू होनी चाहिए -</b> आयोग द्वारा निशक्तता/युद्ध घायल पेंशन के अंशों को शामिल किए जाने के तहत किसी और वृद्धि की सिफारिश नहीं की गई है। (पैरा 10.2.59)	स्वीकृत।																	

11.	<p><b>न तो आरोप्य और न ही उसमें वृद्धि (एनएएनए) मामलों में निश्चिता पेंशन दी जाए –</b></p> <p>आयोग यह सिफारिश करता है कि ऐसे विनियम जिनमें सेवा पर आरोप्य अथवा इस कारण से उसमें वृद्धि में मौजूदा विनियमों को जारी रखने की सिफारिश करते हुए सिफारिश करता है कि यह प्राधिकारियों का काम है कि वे एक तर्कसंगत आदेश के माध्यम से प्रमाणित करें कि निश्चिता न तो सैन्य सेवा पर आरोप्य है और न ही इस कारण उसमें वृद्धि (एनएएनए) हुई है। (पैरा 10.2.61)</p>	स्वीकृत।
12.	<p><b>ऐसे मामलों में युद्ध घायल पेंशन जहां कार्मिक को सेवा में बनाए रखा गया हो –</b></p> <p>आयोग ऐसे कार्मिकों की मौजूदा भुगतान व्यवस्था में किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं करता है जो युद्ध घायल हों तथा जिन्हें सेवा में बनाए रखा गया हो। (पैरा 10.2.63)</p>	स्वीकृत।
13.	<p><b>अशक्त रक्षा कार्मिकों को एकमुश्त अनुग्रह मुआवजा –</b></p> <p>आयोग ने शतप्रतिशत निश्चिता के लिए मौजूदा एकमुश्त मुआवजे में 9 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक वृद्धि किए जाने की सिफारिश की है। तथापि, यह निश्चिता/युद्ध घायल जो सैन्य सेवा पर आरोप्य हो अथवा इस कारण इसमें वृद्धि हुई हो के कारण बोर्डिड आउट सैन्य कार्मिकों की अनुग्रह राशि के भुगतान के ब्रॉड बैंडिंग की सिफारिश करने में कोई औचित्य नहीं पाता है। (पैरा 10.2.65)</p>	स्वीकृत।
14.	<p><b>कैडेटों को अनुग्रह निश्चिता –</b></p> <p>तथापि, आयोग कैडेटों से संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए शतप्रतिशत निश्चिता के लिए अनुग्रह निश्चिता राशि में मौजूदा 6,300 रुपए प्रतिमाह से वृद्धि करके इसे 16,200 रुपए प्रतिमाह किए जाने की सिफारिश करता है। (पैरा 10.2.67)</p>	स्वीकृत।

**MINISTRY OF DEFENCE**  
(Department of Ex-Servicemen Welfare)

**RESOLUTION**

New Delhi, the 30th September, 2016

**No. 17(1)/2014/D(Pension/Policy).**—The Terms of Reference of the Seventh Central Pay Commission as contained in Ministry of Finance (Department of Expenditure) Resolution No.1/1/2013-E.III (A) dated 28.2.2014, as amended vide Resolution, dated 8.9.2015, inter- alia, included the following:-

“To examine, review, evolve, and recommend changes that are desirable and feasible regarding the principles that should govern the emoluments structure, concessions and facilities/benefits, in cash or kind as well as the retirement benefits of the personnel belonging to the Defence Forces, having regard to the historical and traditional parities, with due emphasis on the aspects unique to these personnel”.

2. The Commission submitted its report to the Government on 19<sup>th</sup> November, 2015. Government has considered the recommendations of the Commission on pensionary benefits to the personnel belonging to the Defence Force contained in Chapter 10.2 of the Report of the Commission and have decided that the recommendations shall be broadly accepted subject to certain modifications.

3. Detailed recommendations of the Commission relating to pensionary benefits and the decisions taken thereon by the Government are listed in the statement annexed to this Resolution.
4. The revised provisions regarding pensionary benefits will be effective from 01.01.2016.

K. DAMAYANTHI, Jt. Secy.

#### ANNEXURE

Statement showing the recommendations of the Seventh Central Pay Commission relating to principles which should govern the structure of pension and other terminal benefits contained in Chapter 10.2 of the Report and the decisions of Government thereon.

Item No.	Recommendation for past Defence Forces personnel	Decision of Government
1	<p><b><u>Revision of Pension of pre 7<sup>th</sup> CPC retirees</u></b></p> <p>The Commission recommends the following pension formulation for Defence Forces Personnel who have retired before 01.01.2016 :-</p> <p>(i) All the Defence Forces who retired prior to 01.01.2016 (expected date of implementation of the Seventh CPC recommendations ) shall first be fixed in the Pay Matrix being recommended by this Commission, on the basis of the Pay Band and Grade Pay at which they retired, at the minimum of the corresponding level in the matrix. This amount shall be raised, to arrive at the notional pay of the retiree, by adding the number of increments he / she had earned in that level while in service, at the rate of three percent. Military Service Pay shall be added to the amount which is arrived at after notionally fitting him in the 7<sup>th</sup> CPC matrix. Fifty percent of the total amount so arrived at shall be the revised pension.</p> <p>(ii) The second calculation to be carried out is as follows. The pension, as had been fixed at the time of implementation of the VI CPC recommendations, shall be multiplied by 2.57 to arrive at an alternate value for the revised pension.</p> <p>(iii) Pensioners shall be entitled to the higher of the two.</p> <p>It is recognized that the fixation of the pension as per formulation (i) above may take a little time since the records of each pensioner will have to be checked to ascertain the number of increments earned in the retiring level. It is, therefore, recommended that in the first instance the pension, may be fixed in terms of formulation (ii) above, till final fixation of the pension under the Seventh CPC matrix is undertaken.</p> <p>(Para 10.2.87 &amp; 10.2.88 of the Report)</p>	<p>Both the options recommended by the 7<sup>th</sup> Central Pay Commission as regards pension revision be accepted subject to feasibility of the implementation. Revision of pension using the second option based on fitment factor of 2.57 be implemented by multiplying the pension drawn on 31.12.2015 immediately. The first option may be made applicable if its implementation is found feasible after examination by the committee comprising Secretary (Pension) as Chairman and Member (Staff) Railway Board Member (Staff) D/o Post, Additional Secretary &amp; FA M/ o Home Affairs and Controller General of Accounts as Members.</p>
2	<p><b><u>Rates of Pension, Family Pension &amp; Special Family Pension</u></b></p> <p>The Commission does not recommend any further increase in the <b>rate of Pension for JCOs/ORs.</b> (Para 10.2.22)</p> <p>No change is being recommended by the Commission for either civilian or defence pensioners in <b>Enhanced Ordinary Family Pension.</b>(Para 10.2.33)</p> <p>No further increase in the existing rate of <b>Special Family Pension</b> is recommended by the Commission.(Para 10.2.35)</p>	<p>Accepted.</p>
3	<p><b><u>Additional Pension and Family Pension to the older pensioners.</u></b></p> <p>No further increase in the existing rate of additional pension and additional family pension with advancing age is recommended by the Commission.(Para 10.2.24)</p> <p>No further increase in the existing rate of additional pension and additional family pension with advancing age is recommended by the Commission.(Para 10.2.37)</p>	<p>Accepted</p>

4	<p><b><u>Pre-2006 Honorary Naib Subedar</u></b></p> <p>This Commission does not find any merit in re-opening an issue that has been clearly settled. Therefore <b>no change</b> is being recommended in this regard. (Para 10.2.26 )</p>	Accepted																	
5	<p><b><u>Defence Security Corps (DSC) personnel.</u></b></p> <p>The Commission does not recommend reduction in the qualifying service for entitlement of second pension to Defence Security Corps (DSC) personnel from 15 to 10 years.(Para 10.2.28)</p>	Accepted																	
6	<p><b><u>Depression in Pension for Qualifying Service</u></b></p> <p>The Commission observes that pension formulation is appropriate and finds no justification for a review of the existing arrangements with regard to pension of Territorial Army personnel.(Para 10.2.30)</p>	Accepted																	
7	<p><b><u>Inclusion of War Injury Element/Disability Element in Computation of Family Pension</u></b></p> <p>The Commission has not recommended any further change in the existing provisions with regard to inclusion of war injury element/disability element in the computation of family pension. (Para 10.2.39)</p>	Accepted																	
8	<p><b><u>Enhancement in rate of disability pension.</u></b></p> <p>The Commission is of the considered view that the regime implemented post VI CPC needs to be discontinued, and recommended a return to the slab based system. The slab rates for disability element for 100 percent disability would be as follows:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rank</th><th>Levels</th><th>Rate per month(INR)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Service Officers</td><td rowspan="2">10 and above</td><td rowspan="2">27000</td></tr> <tr> <td>Honorary Commissioned Officers</td></tr> <tr> <td>Subedar Major /Equivalents</td><td rowspan="3">6 to 9</td><td rowspan="3">17000</td></tr> <tr> <td>Subedar /Equivalent</td></tr> <tr> <td>Naib Subedar /Equivalents</td></tr> <tr> <td>Havildar/Equivalents</td><td rowspan="3">5 and below</td><td rowspan="3">12000</td></tr> <tr> <td>Naik/Equivalents</td></tr> <tr> <td>Sepoy/Equivalents</td></tr> </tbody> </table> <p>(Para 10.2.55)</p>	Rank	Levels	Rate per month(INR)	Service Officers	10 and above	27000	Honorary Commissioned Officers	Subedar Major /Equivalents	6 to 9	17000	Subedar /Equivalent	Naib Subedar /Equivalents	Havildar/Equivalents	5 and below	12000	Naik/Equivalents	Sepoy/Equivalents	Accepted.
Rank	Levels	Rate per month(INR)																	
Service Officers	10 and above	27000																	
Honorary Commissioned Officers																			
Subedar Major /Equivalents	6 to 9	17000																	
Subedar /Equivalent																			
Naib Subedar /Equivalents																			
Havildar/Equivalents	5 and below	12000																	
Naik/Equivalents																			
Sepoy/Equivalents																			
9	<p><b><u>Enhancing the Cover of Disability.</u></b></p> <p>The Commission recommends broad-banding of disability for all personnel retiring with disability, including premature cases/ voluntary retirement cases for disability greater than 20 percent.(Para 10.2.57)</p>	Accepted																	
10	<p><b><u>Additional old age Pension should be Applicable for Disability/War Injury Pension.</u></b></p> <p>No further enhancement by inclusion of elements of disability/ war injury pension has been recommended by the Commission.(Para 10.2.59)</p>	Accepted																	
11	<p><b><u>Neither Attributable Nor Aggravated (NANA) cases, be awarded Disability Pension</u></b></p> <p>The Commission recommends that while the existing regulations involving disability Neither Attributable Nor Aggravated (NANA) by service may continue, it is for the authorities to establish, in each case, through a reasoned order that disability was Neither Attributable Nor Aggravated (NANA) by military service. (Para 10.2.61)</p>	Accepted																	

12.	<p><b><u>War Injury Pension where Individual is Retained in Service</u></b></p> <p>The Commission <u>does not recommend any change</u> in the existing regime of payouts for those with war injury and retained in service. (Para 10.2.63)</p>	Accepted
13.	<p><b><u>Ex-gratia Lump Sum Compensation to Invalided out Defence Personnel.</u></b></p> <p>The Commission has recommended an increase in the existing lump sum compensation of Rs. 9 lakh for 100 percent disability to Rs. 20 lakh. However it finds no justification to recommend broad banding for payment of Ex-gratia award to service personnel boarded out on account of disability/war injury attributable to or aggravated by military service.(Para 10.2.65)</p>	Accepted
14.	<p><b><u>Ex Gratia Disability Award to Cadets.</u></b></p> <p>The Commission, however, keeping in views the facts relating to cadets recommends an increase ex-gratia disability award from the existing Rs. 6,300 per month to Rs. 16,200 per month for 100 percent disability. (Para 10.2.67 )</p>	Accepted